

Indian net users to reach 600m by 2020, says Assocham report

NEW DELHI, PTI: With increased 4G and 3G penetration, the number of Indians using the Internet is expected to reach 600 million by 2020 from 343 million currently, even as several challenges remain in realising the mission of Digital India, according to a report.

Spectrum availability in metros is about a tenth of the same in cities in developed countries. This has put a major roadblock in providing high speed data services and public Wi-Fi penetration remains low, said the Assocham-Deloitte study.

Globally, there is one Wi-Fi hotspot for every 150 citizens. For India to reach that penetration level, over eight million hotspots are needed, of which only 31,000 hotspots are currently available, the report added.

Currently, over 55,000 villages remain deprived of mobile connectivity. This is largely due to the fact that providing mobile connectivity in such locations is not com-



mercially viable for service providers, it said.

“Challenges in policy, such as taxation, right of way and restrictive regulations are major roadblocks in realising the vision of Digital India...lack of clarity in FDI policies, for instance, have impacted the growth of ecommerce,” it said.

The study observed that implementation of Digital India programme has been hampered by various issues, such as projects assigned to PSUs being delayed due to challenges related to skills, experience and technical capabilities. Non-availability of digital services in local languages is

also a major concern, added the study.

“With the proliferation of cloud-based services like DigiLocker, data security has emerged as a major challenge. The data breach in August in which debit card data of over 3.2 million subscribers was stolen highlights the importance of implementing fool-proof security systems,” it pointed out.

The study suggested that effective collaboration with the private sector is critical to the development of the digital infrastructure, noting that innovative engagement models that ensure commercial viability need to be developed jointly through consultation with industry bodies.

Moreover, startups need to be incentivised for the development of the last mile infrastructure and localised services and applications. In rural and remote areas, private sector players should be incentivised to provide last mile connectivity.

India to have 600 m netizens by 2020

New Delhi, December 5

With increased 4G and 3G penetration, the internet user base in India is rapidly growing, and is expected to double to 600 million users by 2020, from the current 343 million, said a study on Monday. Going forward, rural adoption of data-enabled devices is expected to increase with the BharatNet initiative under the Digital India drive, according to the study jointly conducted by Assocham and Deloitte. The study said the internet user base in India has reached over 27 per cent penetration, compared with 50.3 per cent in China. India is the second-largest mobilephone market globally. IANS

NET USERS TO REACH 600M BY 2020: REPORT

New Delhi, 5 December: With higher 4G and 3G penetration, the number of Indians using the Internet is expected to reach 600 million by 2020 from 343 million currently, even as several challenges remain in realising the mission of Digital India.

Spectrum availability in metros is about a tenth of the same in cities in developed countries. This has put a major roadblock in providing high speed data services and public Wi-Fi penetration remains low, said the Assocham-Deloitte study.

Globally, there is one Wi-Fi hotspot for every 150 citizens. For India to reach that penetration level, over 8 million hotspots are needed, of which only 31,000 hotspots are currently available, the report added. PII

अध्ययन

ग्रामीण आबादी के डाटा आधारित सेवाओं को अपनाने की रफ्तार बढ़ेगी

2020 तक होंगे 60 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर (एजेसियां)। स्मार्टफोन की सुलभता के कारण देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या की तेजी से बढ़ती हुई 27 प्रतिशत पर पहुंच गयी है, जिसके वर्ष 2020 तक 60 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। उद्योग संगठन एसोचैम की डेलॉयट के साथ मिलकर किये गये एक अध्ययन में यह बात सामने आयी है। अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 34 करोड़ 30 लाख है, जो कुल आबादी का 27 प्रतिशत है।

इस मामले में भारत अभी चीन से काफी पीछे है, जहां 50.3 प्रतिशत आबादी की इंटरनेट तक पहुंच है। वर्ष 2020 तक यह संख्या बढ़कर 60 करोड़ पर पहुंच जाने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत भारत नेट के बढ़ते दायरे के साथ ग्रामीण आबादी के डाटा आधारित सेवाओं को अपनाने की रफ्तार बढ़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बाजार है। यहां मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या एक अरब से ज्यादा है। इनमें स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 24 करोड़ के करीब है जो वर्ष 2020 तक दुगुने से भी ज्यादा होकर 52



करोड़ पर पहुंच जायेगी। एसोचैम ने बताया कि विकसित देशों के मुकाबले भारत के मेट्रो शहरों में स्मार्टफोन की उपलब्धता मात्र 10 प्रतिशत है। इससे हाईस्पीड डाटा सेवाएं मुहैया कराने में बड़ी दिक्कत आ रही है। सार्वजनिक वाई-फाई की उपलब्धता काफी कम है। गांवों में इंटरनेट सेवा देने में दूरसंचार सेवा प्रदाता अभी भी काफी पीछे हैं। देश भर में 55 हजार से अधिक गांवों में इंटरनेट

उपलब्ध नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि कंपनियों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल इंडिया के रास्ते में कुछ नीतिगत चुनौतियां हैं, जैसे कराधान, राइट ऑफ वे, बाधक नियम आदि। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियों में स्पष्टता की कमी के कारण ई-कॉमर्स का विकास तेजी से नहीं हो रहा है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को परियोजनाओं के आवंटन पर भी सवाल उठते हुये कहा गया है कि इन कंपनियों के पास कौशल, अनुभव तथा तकनीकी दक्षता की कमी के कारण परियोजनाओं में देरी होती है जो डिजिटल इंडिया की राह में अतिरिक्त बाधा है।

2020 तक 60 करोड़ करेंगे इंटरनेट का यूज

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली. शहरों से लेकर गांवों तक स्मार्टफोन की उपलब्धता आसान होने से इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई कुल आबादी का 27 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसे देखते हुए 2020 तक यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंच सकती है। यह जानकारी उद्योग संगठन एसोचैम और डेलॉय के एक रिसर्च से सामने आई है। वर्तमान में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 34 करोड़ 30 लाख है।

2020 तक होंगे 60 करोड़ इंटरनेट यूजर

नई दिल्ली ■ वार्ता

स्मार्टफोन की आसान मौजूदगी के कारण देश में इंटरनेट यूजरों की संख्या की तेजी से बढ़ती हुई 27 फीसद पर पहुंच गई है, जिसके साल 2020 तक 60 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। उद्योग संगठन एसोचेम की डेलॉयट के साथ मिलकर किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 34 करोड़ 30 लाख है, जो कुल आबादी का 27 फीसद है। इस मामले में भारत अभी चीन से काफी पीछे है, जहां 50.3 फीसद आबादी की इंटरनेट तक पहुंच है।

साल 2020 तक यह संख्या बढ़कर 60 करोड़ पर पहुंच जाने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत भारत नेट के बढ़ते दायरे के साथ ग्रामीण आबादी के डाटा



आधारित सेवाओं को अपनाने की रफ्तार बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बाजार है। यहां मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या एक अरब से ज्यादा है। इनमें स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 24 करोड़ के करीब है जो साल 2020 तक दुगुने से भी ज्यादा होकर 52 करोड़ पर पहुंच जाएगी।

एसोचेम ने बताया कि विकसित देशों के मुकाबले भारत के मेट्रो शहरों में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता

मात्र 10 फीसद है। इससे हाईस्पीड डाटा सेवाएं मुहैया कराने में बड़ी दिक्कत आ रही है। सार्वजनिक वाई-फाई की उपलब्धता काफी कम है। गांवों में इंटरनेट सेवा देने में टेलीकॉम कंपनियां अभी भी काफी पीछे हैं। देश भर में 55 हजार से अधिक गांवों में इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि कंपनियों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल इंडिया के रास्ते में कुछ नीतिगत चुनौतियां हैं, जैसे कराधान, राइट ऑफ वे, बाधक नियम आदि। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियों में स्पष्टता की कमी के कारण ई-कॉमर्स का विकास तेजी से नहीं हो रहा है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की परियोजनाओं के आवंटन पर भी सवाल उठाते हुए कहा गया है कि इन कंपनियों के पास कौशल, अनुभव और तकनीकी

दक्षता की कमी के कारण परियोजनाओं में देरी होती है जो डिजिटल इंडिया की राह में अतिरिक्त रुकावट है।

इनके अलावा इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल के बारे में लोगों में जानकारी का अभाव और डिजिटल सेवाओं का स्थानीय भाषाओं में न होना भी डिजिटल इंडिया के रास्ते का रोड़ा है। एसोचेम ने कहा कि इस साल अगस्त में 32 लाख उपभोक्ताओं के डाटा चोरी हो जाना सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत को रेखांकित करता है। डिजिटल अवसंरचना के निर्माण में निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी अहम है। रिपोर्ट में ग्रामीण और सुदूर इलाकों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन पैकेज दिया जाना चाहिए। इन इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने के लिए उपग्रह संचार उपचारों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

2020 तक होंगे 60 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता

नई दिल्ली (एजेंसी)

स्मार्टफोन की सुलभता के कारण देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या की तेजी से बढ़ती हुई 27 प्रतिशत पर पहुँच गयी है, जिसके वर्ष 2020 तक 60 करोड़ पर पहुँचने की उम्मीद है।

उद्योग संगठन एसोचैम की डेलॉयट के साथ मिलकर किये गये एक अध्ययन में यह बात सामने आयी है। अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 34 करोड़ 30 लाख है, जो कुल आबादी का 27 प्रतिशत है। इस मामले में भारत अभी चीन से काफी पीछे है, जहाँ 50.3 प्रतिशत आबादी की इंटरनेट तक पहुँच है। वर्ष 2020 तक यह संख्या बढ़कर 60 करोड़ पर पहुँच जाने की उम्मीद है।

इसमें कहा गया है कि सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत भारत नेट के बढ़ते दायरे के साथ ग्रामीण आबादी के डाटा आधारित सेवाओं को अपनाने की रफ्तार बढ़ेगी।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया का दूसरा

सबसे बड़ा मोबाइल फोन बाजार है। यहाँ मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या एक अरब से ज्यादा है। इनमें स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 24 करोड़ के करीब है जो वर्ष 2020 तक दुगुने से भी ज्यादा होकर 52 करोड़ पर पहुँच जायेगी।

एसोचैम ने बताया कि विकसित देशों के मुकाबले भारत के मेट्रो शहरों में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता मात्र 10 प्रतिशत है। इससे हाईस्पीड डाटा सेवाएँ मुहैया कराने में बड़ी दिक्कत आ रही है। सार्वजनिक वाई-फाई की उपलब्धता काफी कम है। गाँवों में इंटरनेट सेवा देने में दूरसंचार सेवा प्रदाता अभी भी काफी पीछे हैं। देश भर में 55 हजार से अधिक गाँवों में इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि कंपनियों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल इंडिया के रास्ते में कुछ नीतिगत चुनौतियाँ हैं, जैसे कराधान, राइट ऑफ वे, बाधक नियम आदि। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियों में स्पष्टता की कमी के कारण ई-कॉमर्स का विकास तेजी से नहीं हो

रहा है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को परियोजनाओं के आवंटन पर भी सवाल उठते हुये कहा गया है कि इन कंपनियों के पास कौशल, अनुभव तथा तकनीकी दक्षता की कमी के कारण परियोजनाओं में देरी होती है जो डिजिटल इंडिया की राह में अतिरिक्त बाधा है। इनके अलावा इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल के बारे में लोगों में जानकारी का अभाव तथा डिजिटल सेवाओं का स्थानीय भाषाओं में न/न होना भी डिजिटल इंडिया के रास्ते का रोड़ा है।

एसोचैम ने कहा कि इस साल अगस्त में 32 लाख उपभोक्ताओं के डाटा चोरी हो जाना सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत को रेखांकित करता है। डिजिटल अवसंरचना के निर्माण में निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में ग्रामीण और सुदूर इलाकों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन पैकेज दिया जाना चाहिये। इन इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुँचाने के लिए उपग्रह संचार उपचारों का इस्तेमाल किया जा सकता है।